लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1647

10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पटसन उद्योग

1647. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पटसन उद्योग पूरी तरह से सरकारी क्रयादेश पर निर्भर हैं और क्रयादेश में गिरावट के कारण उद्योगों और कामगारों को उत्पादन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे पटसन बाजार को बचाने और पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार और ओडिशा के किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिमी बंगाल के रुग्ण पटसन उद्योगों, जो कुल राष्ट्रीय क्षेत्र और उत्पादन का अधिकतम 80.7 प्रतिशत और 83.7 प्रतिशत है, को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग) सरकार, जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम 1987 के तहत, खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए बी-ट्विल जूट बैग की खरीद के माध्यम से जूट उद्योग को सहायता प्रदान करती है, जो उद्योग के कुल उत्पादन का 80% है।

इसके अलावा, भारत सरकार पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और ओडिशा सहित पूरे देश के जूट किसानों की सुरक्षा हेतु प्रति वर्ष कच्ची जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। इसके अलावा, जूट किसानों को अधिक उपज वाली किस्म के प्रमाणित जूट बीज और रेटिंग पाउडर प्रदान करने के लिए जूट-बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास (जूट-आईकेयर) योजना लागू की गई है, ताकि कच्ची जूट की उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायता मिल सके।

***